



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 774 राँची, बुधवार

8 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त, 2018

संख्या-13/न्या० विविध-04/2018 का० 5888-- निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-34(1) के द्वितीय परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार न्यायिक सेवा की कार्य प्रकृति को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुरूप झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती में दिव्यांगजन को देय क्षैतिज आरक्षण के संबंध में निम्न प्रकार प्रावधान करती है-

- (क) निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा ।
- (ख) दृष्टिहीन, बधिर, प्रमस्तिष्क घात, स्वलीनता एवं उक्त अधिनियम की धारा 34(1) के क्रमांक-(d) एवं (e) में वर्णित अन्य निःशक्तता से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगजन को देय क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

(ग) दिव्यांगजन के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अन्तर्गत (i) निम्न दृष्टि (Low vision) से पीड़ित अभ्यर्थी के लिए 1 प्रतिशत, (ii) आंशिक बधिर (Low hearing) से पीड़ित अभ्यर्थी के लिए 1 प्रतिशत तथा (iii) चलन निःशक्तता (Locomotor disability) (प्रमस्तिष्क घात को छोड़कर) से पीड़ित अभ्यर्थी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाय, बशर्ते कि प्राधिकृत चिकित्सा पर्सन उन्हें सहायक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक की सहायता से इस पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए योग्य घोषित करता हो ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।
